

नवोदय

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की तिमाही गृह पत्रिका | दिसंबर 2021



पी.एस.बी

NAVODAYA

Punjab & Sind Bank Quarterly House Journal | December 2021



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ)

ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜੀਵਨ - ਖ਼ਯੇਯ ਹੈ



Punjab & Sind Bank

(A Govt. Of India Undertaking)

Where service is a way of life

Top 10 Zones for General Insurance Issued Business

YTD from 01-Apr-2021 to 31-Dec-2021



1st



Zone Gandhinagar
Rs. 5.50 Lakh Comm.
(95% of YTD)

2nd



Zone Patiala
Rs. 16.44 Lakh Comm.
(89% of YTD)

3rd



Zone Lucknow
Rs. 14.85 Lakh Comm.
(81% of YTD)

4th



Zone Kolkatta
Rs. 13.18 Lakh Comm.
(79% of YTD)

5th



Zone Hoshiarpur
Rs. 9.11 Lakh Comm.
(78% of YTD)

6th



Zone Guwahati
Rs. 3.91 Lakh Comm.
(73% of YTD)

7th



Zone Bhatinda
Rs. 10.02 Lakh Comm.
(73% of YTD)

8th



Zone Dehradun
Rs. 7.28 Lakh Comm.
(61% of YTD)

9th



Zone Jaipur
Rs. 7.47 Lakh Comm.
(58% of YTD)

10th



Zone Bhopal
Rs. 7.12 Lakh Comm.
(56% of YTD)

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ)

ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜੀਵਨ - ਖ਼ਯੇਯ ਹੈ



Punjab & Sind Bank

(A Govt. Of India Undertaking)

Where service is a way of life

Top 10 Zones for Life Insurance Issued Business

YTD from 01-Apr-2021 to 31-Dec-2021



1st



Zone Jalandhar
Rs. 59.93 Lakh Comm.
(133% of YTD)

2nd



Zone Hoshiarpur
Rs. 37.49 Lakh Comm.
(122% of YTD)

3rd



Zone Kolkatta
Rs. 47.42 Lakh Comm.
(105% of YTD)

4th



Zone Ludhiana
Rs. 47.28 Lakh Comm.
(103% of YTD)

5th



Zone Jaipur
Rs. 31.33 Lakh Comm.
(87% of YTD)

6th



Zone Bhatinda
Rs. 31.42 Lakh Comm.
(87% of YTD)

7th



Zone Patiala
Rs. 42.95 Lakh Comm.
(86% of YTD)

8th



Zone Gurdaspur
Rs. 38.35 Lakh Comm.
(84% of YTD)

9th



Zone Chandigarh & Panchkula
Rs. 50.61 Lakh Comm.
(81% of YTD)

10th



Zone Amritsar
Rs. 42.79 Lakh Comm.
(74% of YTD)



पंजाब एंड सिंध बैंक
PUNJAB & SIND BANK

(भारत सरकार का उपक्रम/ Government of India Undertaking)



एस कृष्णन
प्रबंध निदेशक और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



S Krishnan
Managing Director and
Chief Executive Officer

Dear PSBians,

As the sun sets for 2021 and we step into the dawn of 2022, I wish the year belongs to Punjab & Sind Bank. The year 2021 was the *year of transformation* for the bank. It created the launchpad for the bank and all of us to show to the world हम में है दम, हम नहीं किसी से कम।

In my earlier communication I said that 2021-22 will be the year of Punjab & Sind Bank. I feel immensely proud that each one of the PSBians toiled hard to turn the bank around and as a result of that, the bank posted Net Profit for three consecutive quarters since March 2021. Friends, the journey to the ultimate goal of making Punjab & Sind Bank *numero uno* has just begun. We need to keep marching ahead with utmost zeal, commitment and dedication, keeping only one thing in mind बैंक से ऊपर कुछ नहीं।

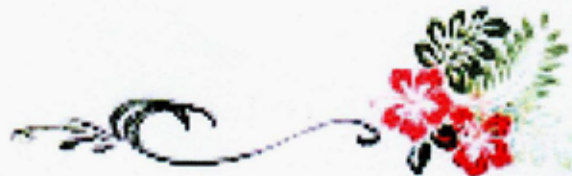
The first three months (January to March) of the new year 2022 will be most crucial for the bank. We need to put-in all out efforts to achieve the business targets of Rs.185000 crore for the FY 2021-22. To achieve that, we need to subsume our personal priorities to the corporate goals of our beloved bank. अपना सब कुछ न्योछावर करना है, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने मान-सम्मान के लिए क्योंकि बैंक से हम हैं, हमसे बैंक नहीं। Friends, we all can create a history for our beloved bank, which the generations to come will be proud of. As Dr APJ Adhul Kalam said "अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।

Friends, I firmly believe that each one of PSBian is a bundle of exponential capabilities, courage & determination and no target or goal is beyond our reach. We just need to focus and make determined & persistent efforts.

कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा
अर्जुन के तीर सा साध, मरुथल से भी जल निकलेगा
मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से फल निकलेगा
कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा

I wish PSBians and their families a very happy and prosperous 2022. Stay safe, stay healthy.

S Krishnan



मुख्य संरक्षक

श्री एस. कृष्णन

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक

श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र

कार्यकारी निदेशक

डॉ रामजस यादव

कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री कामेश सेठी

महाप्रबंधक

सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

श्री राजेश सी पांडे

महाप्रबंधक

डॉ. नीरू पाठक

प्रबंधक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक गृह पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखक के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : जैना ऑफ़सेट प्रिंटेर्स

ए 33/2, साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,

गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश

फोन नं. : 98112 69844

ई-मेल: jainoffsetprinters@gmail.com

विषयसूची/Index

1. Message by MD & CEO	1
2. संपादक मंडल / विषय सूची	2
3. संपादकीय	3
4. शुभकामनाएं एवं सुझाव	4
5. पर्यावरण संरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है?	5-7
6. APY-Not Just about pension....	8-10
7. Customer meet	11
8. सतर्कता जागरूकता सप्ताह	12-13
9. Vigilance Angle	14-15
10. Neo Banks : Arrival of Challenger Banks	16-19
11. Review Meetings	20-21
12. गुरुपर्व का आयोजन	22-23
13. क्रेडिट आउटरिच कार्यक्रम	24
14. Job Performance	25-27
15. Financial Awareness Camp	28
16. Marketing Campaign	29
17. Important circulars issued by different deptt. Of H.O. (01.10.2021 to 31.12.2021)	30-31
18. Precautionary Measures for Disciplinary Actions	32-35
19. Door to Door Campaign	36
20. श्रद्धाचार - मूल तथा उन्मूलन	37-38
21. PSB UniC-A Unique App for everything you need	39-40
22. Branch Manager Review Meeting	41
23. Budget - 2022	42
24. Retail Lending Camp	43
25. नववर्ष	44



संपादकीय

साथियो,

बैंक की गृह पत्रिका नवोदय के नवीनतम अंक के माध्यम से आपसे एक बार फिर संवाद स्थापित करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम, आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं। कोरोना महामारी से लगातार संघर्ष करते हुए तथा बैंकिंग परिवर्तन के कठिन दौर से गुजरते हुए हम तिमाही गृह पत्रिका नवोदय के नवीन अंक का प्रकाशन कर रहे हैं। महामारी का संकट अभी टला नहीं है, इस चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर हमारी बैंकिंग आर्मी अर्थात् आप सभी सकुशल रहकर अपनी असीमित ऊर्जा तथा नवीन तकनीक के साथ बैंक को अपनी सेवाएं दें।

बैंक की द्विभाषी गृह पत्रिका नवोदय का अभी यह चतुर्थ अंक ही है लेकिन आपके सुझाव और प्रतिक्रिया बता रही है कि इसकी आप सभी को प्रतीक्षा रहती है वस्तुतः यह पत्रिका बैंककर्मियों की सृजनात्मक क्षमता को उजागर करने के लिए एक उचित मंच तो है ही साथ ही बैंक की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी देती है। पत्रिका के प्रस्तुत अंक में मुख्यतः बैंक में आयोजित विभिन्न गतिविधियों, बैंक के विभिन्न उत्पादों, नीतियों, महत्वपूर्ण परिपत्रों के साथ ऐसे लेखों को समाहित किया गया है जो न केवल आधुनिक बैंकिंग से आपको परिचित कराएंगे बल्कि आपके बैंक के कार्यों में भी सहायक होंगे। **Vigilance Angle, Precautionary measures for Disciplinary Actions, APY- Not Just about Pension.....but an Exceptional Investment**, पर्यावरण संरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आदि ऐसे ही अत्यंत ज्ञानवर्धक लेख पत्रिका के विशेष आकर्षण हैं।

मुझे विश्वास है कि पाठकगण इसे उपयोगी और सूचनाप्रद पाएंगे। बैंकिंग के विविध पहलुओं को समेटे यह पत्रिका आपको कैसी लगी, इसके अनवरत सुधार की दिशा में आपकी प्रतिक्रिया एवं सुझावों का हमें सदैव इंतजार रहेगा।

नववर्ष की शुभकामनाओं और आपके स्वास्थ्य की मंगलकामना सहित,

(कामेश सेठी)

महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक

शुभकामनाएं एवं सुझाव

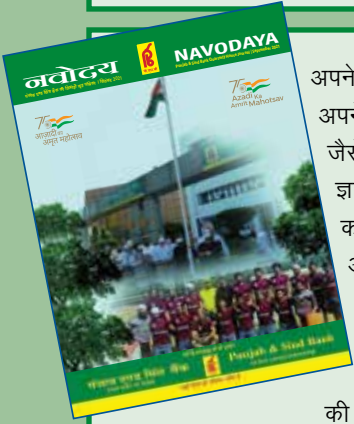
आपके बैंक की तिमाही गृह पत्रिका "नवोदय" का नवीनतम अंक प्राप्त कर प्रसन्नता हुई। सर्वप्रथम पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं स्वीकार करें।

नवोदय के इस अंक में बैंक की विभिन्न योजनाओं, महत्वपूर्ण परिपत्रों एवं बैंक की गतिविधियों को बखूबी दर्शाया गया है, पत्रिका में प्रकाशित बैंकिंग तथा वित्त संबंधी आलेखों की प्रस्तुति बेहतर ढंग से की गई है। विशेषकर पत्रिका में प्रकाशित आलेख बैंकों में वसूली प्रबंधन और उनका नियोजन कैसे करें, "Door Step Banking (DSB) Services through Universal touch Points (UTP)", "National Asset Reconstruction Company Limited – An Introduction", वर्तमान परिदृश्य में बैंकिंग क्षेत्र, आदि काफी ज्ञानवर्धक एवं सूचनाप्रद हैं, पत्रिका में प्रकाशित अन्य आलेख भी रोचक एवं पठनीय हैं।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए पूरी संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएं।

संजय सिंह

प्रमुख राजभाषा एवं संसदीय समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा



अपने बैंक की गृह पत्रिका नवोदय का सितंबर, 2021 अंक प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम तो इसके लिए धन्यवाद! यह पत्रिका अपने आप में इतनी स्तरीय है कि इसे पढ़ने से इसके नाम के अनुरूप ही नयी चेतना, नए ज्ञान का उदय होता है। जैसे ही यह मुझे प्राप्त होती है एक बार में ही इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इस बार भी नवोदय बेहद ज्ञानवर्धक और रचनात्मक लगी। नवोदय का सितंबर अंक बैंक संबंधी नवीनतम जानकारी, तकनीक और ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है। महाप्रबंधक महोदय श्री गोपाल कृष्ण का लेख 'बैंकों में वसूली प्रबंधन और उनका नियोजन कैसे करें' वर्तमान परिदृश्य में बेहद प्रासंगिक है। महाप्रबंधक महोदय श्री कामेश सेठी का लेख 'Tips to New Branch Managers' का लेख न सिर्फ अपने बल्कि सभी बैंकों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। डॉ. नीरू पाठक का लेख 'खेलों की उन्नति में बैंक का योगदान' पढ़कर गौरव की अनुभूति होती है कि देश में खेलों के विकास में अपने बैंक की भूमिका कितनी उल्लेखनीय रही है। बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अपने बैंक की स्थिति तथा अंचलों के कार्यों का मूल्यांकन इस पत्रिका को पूर्ण रूप से बैंक की गृह पत्रिका बनाती है। पत्रिका की

साज-सज्जा, प्रिंट आकर्षक है।

अतः नवोदय के संपादक मंडल ऐसे ज्ञानवर्धक, पठनीय व महत्वपूर्ण पत्रिका के प्रकाशन के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। धन्यवाद!

चमन लाल शीहमार

आंचलिक प्रबंधक, अंचल दिल्ली-01

आपके कुशल मिर्देशन व मार्गदर्शन में प्रकाशित की जा रही बैंक पत्रिका 'नवोदय' का रंग-बिरंगा छटा बिखेरता बहुआयामी अंक प्राप्त हुआ-आभार। बैंकिंग क्षेत्र में इस प्रकार की पत्रिका का एक विशेष व महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज बैंकिंग व्यवस्था हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है जो कि काफी जोखिम भरा कार्य है। ऐसे में बैंक की विविधताओं, प्राप्तियों व उपलब्धियों को हर अंतराल में नियमित रूप से बैंक पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत करना सचमुच प्रशंसनीय कार्य है। निःसंदेह पत्रिका के संपादक-मंडल ने इसे सफलता पूर्वक सम्पन्न कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ।

डॉ चरनजीत सिंह,

सेवा निवृत्त मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

बैंक पत्रिका नियमित रूप से मिल रही है- आभार।

हर बार की तरह वैविध्यता से ओतप्रोत, ज्ञानवर्धक जानकारी व रोचक सामग्री लिए नवोदय दिनों-दिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नवीनतम अंक में यथासंभव बैंक की आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को समाहित किया गया है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लेखों के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की गई है। पत्रिका की साज-सज्जा व पृष्ठ-संयोजन देखते ही बनता है। आपके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में पत्रिका को नवीन आयाम प्रदान किए हैं। पत्रिका से जुड़े सभी सहभागियों तथा संपादक मंडल की कार्य-निष्ठा के लिए बधाई व शुभकामनाएं।

जगमोहन सिंह

सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक, कार्यकारी निदेशक सचिवालय, नई दिल्ली

पर्यावरण संरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है?



चमन लाल शीहमार

प्रकृति के समस्त प्राणियों के मध्य मनुष्य अपनी विशेष पहचान रखता आया है। कभी पत्थरों से आग जलाने वाले हम मानवों ने आज दूसरे ग्रहों पर अपने कदम रखने शुरू कर दिए हैं। हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमने अपनी बुद्धि, विवेक और क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया है। अपने ज्ञान और तर्क के लौ से जड़ता तथा अंधविश्वास की कालिमा को मिटाते आए हैं। भौतिक दुनिया को और बेहतर एवं मानवों के अनुकूल बनाने के प्रयासों के दौरान हमारी गति दिनों दिन तीव्र होती चली गई। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब किसी की गति आवश्यकता से अधिक तीव्र होती है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने या मंजिल से भटकने के खतरे ज्यादा होते हैं। इसलिए विवेक का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। दुनिया को भौतिक नजरिए से सुविधापूर्ण बनाने में हमारी गति ऐसी

ही रही है। वैज्ञानिक शोध के विकास, औद्योगिकीकरण आदि के कारण हम मानवों ने पिछले पांच सौ वर्षों में अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। पश्चिम देशों का योगदान इसमें विशेष तौर पर उल्लेखनीय रहा है। परंतु, इन सफलताओं ने मानवों के विवेक को धुमिल कर दिया। प्रकृति के कोख से जन्में मनुष्य ने प्रकृति को ही

चुनौती दे डाली। प्रकृति को अपने अनुरूप रखने के लिए प्रकृति को ही जीतने का नारा हम मनुष्यों ने दे डाला। प्रकृति से पाने और पाने की लालच ने हमारे और प्रकृति के बीच एक तनावपूर्ण संबंध खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रकृति मनुष्य की जरूरतें पूरा कर सकती हैं, मनुष्य का लालच नहीं। गांधीजी के इस महत्वपूर्ण कथन का आशय स्पष्ट है— मानव के लालची स्वभाव ने प्रकृति का ऐसा दोहन कर डाला कि मानों अब प्रकृति के सब्र की सीमा भी खत्म होने लगी है। समय समय पर प्रकृति ने यह संदेश हमें दिया भी है परंतु हम! हम मनुष्य अपने ज्ञान के दंभ और लाभ के लोभ के धुन में ऐसे रमते चले गए कि प्रकृति का कोई भी संदेश हम अनसुना करते चले गए।



पिछले कुछ दशकों से पर्यावरण संकट जैसे शब्दों ने बुद्धिजीवियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर पर्यावरण में होने वाले अकारण बदलावों पर गंभीर चिंतन मनन किया जाने लगा है। प्रश्न उठता है ऐसा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? कभी प्रकृति को जीतने का दंभ भरने वाले मनुष्यों ने क्यों प्रकृति या पर्यावरण पर एक अलग प्रकार की चिंता प्रकट करने लगे? हमें इन प्रश्नों को समझना होगा क्योंकि इन्हीं में पर्यावरण और मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति का पता चल सकेगा।

पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा से लेकर पीने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए आवास दिलाता है। किसी भी जीवित जीव के चारों ओर पाए जाने वाले प्राणी, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण अर्थात् environment शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेर से हुई है जिसका अर्थ है 'पड़ोस'। अतः मनुष्य के आस पास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। हिंदी में पर्यावरण शब्द 'परि आवरण' शाब्दिक अर्थ में निहित है जिसका अर्थ

चारों ओर का परिवेश। अतः किसी भी भाषा में पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर फैले ऐसे वातावरण या परिवेश को कहते हैं जिसमें वनस्पतियों, प्राणियों, मानवों सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित गतिविधियां निहित हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके पारिस्थितिकी के मध्य एक संबंध स्थापित रहता है जो बेहद संतुलित होता है। पर्यावरण के संतुलन के लिए यह बेहद जरूरी है कि पर्यावरण के मौलिक नियमों, गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है और समस्या यहीं से शुरू से होती है। अपनी जरूरतों को पूरा करते करते हमने न जाने कितनी प्रजातियों को लुप्त कर दिया, न जाने कितनी नदियों की कभी धारा

बदल दी तो कभी उन्हें सुखा ही कर दिया तो कभी वायुमंडल का तापमान ही बढ़ा दिया। हमारी बढ़ती आबादी के साथ हरियाली वन क्षेत्र घटते चले गए। शहरीकरण बढ़ते बढ़ते जंगलों को निगलने लगी। धातुओं, कोयला के अत्यधिक उत्खनन ने न सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य को बिगाड़ दिया बल्कि वहां रहने वाले निवासियों के भविष्य को भी असुरक्षित कर दिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परिवर्तन तो भौतिक जगत की शाश्वत सच्चाई है जो सतत चलती रहती है परंतु जब यह स्वतः होती है तब यह संतुलित होती है परंतु जब यह हम मानवों के द्वारा होती है तब यह कई प्रकार की विभीषिकाओं को आमंत्रित करती है। आज हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन की तीन मूलभूत तत्व वायु, जल एवं मृदा खतरे में है।



वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और बेहिसाब वनों की कटाई से मृदा अपरदन के कारण पर्यावरण के इन तीन आधारभूत तत्वों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है और ये संकट अंततः हमारे अस्तित्व पर ही कुठाराघात करेगा। हाल के वर्षों में भारत समेत पूरी दुनिया में स्मॉग, धुंध की एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। ये कुछ और नहीं हमारे ही अविवेकपूर्ण कृत्यों का ही प्रतिफलन है। पेट्रोल, डीजल की गाड़ियों से निकला धुआं लैड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के आक्साइड सूर्य के प्रकाश से मिलकर रसायनिक कोहरे को उत्पन्न करते हैं जो किसी भी जीव के फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक है। कल कारखानों से निकले केमिकल्स, रसायनिक कचरों ने नदियों के सतत प्रवाह को गंभीर क्षति पहुँचाई है। हालात ये है कि भारत की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी गंगा के निर्मल प्रवाह को बचाने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलानी पड़ रही है। यमुना नदी की हालत देख कर ऐसा लगता है मानों हम मानवों ने नदियों से बैर ही ठान ली हो। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नदियां स्वयं तो नहीं सूख रही हैं। ये हम ही हैं जो मानवों की सभ्यता को पल्लवित करने वाली नदियों के खिलाफ ही कार्य करते जा रहे हैं। पर्यावरण का फेफड़ा कहे जाने वाले वनों की बेहिसाब कटाई भी हमारी अदूरदर्शिता को ही दर्शाता है। वनों की बेहिसाब कटाई से मृदा अपरदन की समस्या खड़ी हो रही है। उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है, हल्की बारिश में ही गांव-कस्बे-शहर डूबे जा रहे हैं। इनसे जान-माल की बड़ी क्षति होती है। भारत समेत पूरी दुनिया ने पिछले दो-तीन दशकों में अनेक प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। इन आपदाओं को झेलने के पश्चात हमें यह समझ में आया कि जिस पर्यावरण से हम सब कुछ पाना चाहते हैं हमें उसके संरक्षण के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी होगी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेक और दूरदर्शी चिंतन के साथ करना होगा। स्वच्छ वायु, निर्मल जल और सुरक्षित पर्यावरण को हमारे मूलभूत अधिकारों की तरह प्राथमिकता देनी होगी।

हम जानते हैं कि प्रकृति में हर एक जीव का विशिष्ट कार्य होता है, विशिष्ट भोजन और विशिष्ट आवास होता है। पर्यावरण को ध्यान से समझने पर यह बात स्पष्ट होती है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में जीवों के मध्य अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। इन जीवों के मध्य ऐसे संबंध

विकसित होते हैं जो इनके अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खाद्य श्रृंखला इसका एक उदाहरण है। हम मानवों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कई जीवों का शिकार इतना अधिक कर दिया कि वे जीव या तो विलुप्त ही हो गए या विलुप्त होने के कगार पर आ गए। हमने ये बिना सोचे समझे ही किया कि किसी एक जीव के विलुप्त होने से पूरी पारिस्थितिकी पर क्या असर पड़ेगा। अपनी लालच को पूरा करने में हम मानवों ने जैव मंडल के संतुलन को ही विकृत कर दिया।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति पहला गंभीर प्रयास सन् 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव दिया गया और ठीक इसके दो साल के बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरु किया गया। सन् 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया के 174 देशों ने भाग लिया। इसके बाद सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इन सम्मेलनों का संदेश यही था कि दुनिया के समक्ष पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया जाए। पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भारत समेत अन्य दुसरे देशों ने अपने देशों में वन एवं वन-जीव आदि को संरक्षित रखने के लिए अनेक नियम-कानून बनाए। जैसे भारत ने 1986 में पर्यावरण रक्षा अधिनियम, 1986 बनाया। इसके पहले भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 बनाया। आगे चलकर भारत ने 2010 में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 बनाया जो कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक मील का पत्थर है। संक्षेप में इस प्राधिकरण के बारे में कहा जाए तो यह वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर देखें तो भारत का प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभी तक सराहनीय रहा है। परंतु यह काफी नहीं है। जैसे जैसे भारत विकास कर रहा है पर्यावरण संरक्षण की चुनौती भी बढ़ रही है। यहां एक बात गौरतलब है कि पर्यावरण संरक्षण की चुनौती एक वैश्विक चुनौती है और इसमें सिर्फ भारत या किसी एक देश के सराहनीय प्रयासों से ज्यादा कुछ नहीं हासिल नहीं हो पाएगा। अतः पर्यावरण की समस्या में दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर साथ मिलकर चलने से आशातीत सफलता मिल पाएगी।



पर्यावरण के लिए ग्रीन हाउस गैस एक गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। ये ऐसे गैस हैं जिन्होंने पृथ्वी के तापमान को असंतुलित करना शुरू कर दिया है। इनसे पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो गया है और इसके कई गंभीर दुष्परिणाम दिखने शुरू भी हो गए हैं। कई जीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियरों के बर्फ पिघलने शुरू हो गए हैं। महासागरों के जल स्तर में वृद्धि होने लगी है और ऐसी आशंका है कि विश्व की एक बड़ा आबादी के रहने वाले स्थल क्षेत्र निकट भविष्य में जलमग्न हो जाएगी। ग्लेशियरों के बर्फ पिघल जाने से गंगा-सिंधु-ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों के सूख जाने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है और सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसी नदियों के सूख जाने से विश्व की कितनी बड़ी आबादी किस स्तर तक प्रभावित हो सकती है। ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड और ओजोन गैस आते हैं। इन गैसों की एक विशेषता है कि इनमें प्रकाश के उष्मा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। औद्योगिकीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण वायुमंडल में भी इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान कार्बन डाई आक्साइड का रहा है। अगर हम सौर मंडल के अन्य ग्रहों और हमारी पृथ्वी के बीच मुख्य अंतर को देखे तो हम पाएंगे कि हमारी पृथ्वी में सभी आवश्यक गैसों की मात्रा में अद्भुत संतुलन है। नाइट्रोजन, आक्सीजन, कार्बन डाई आक्साइड एवं अन्य गैसों की मात्रा इतनी संतुलित है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। अतः सभी आवश्यक गैसों की मात्रा का संतुलन एक बेहद संवेदनशील मामला है। औद्योगिकीकरण के बढ़ते रफ्तार के कारण पिछले तीन-चार दशकों में कार्बन डाई आक्साइड का उत्सर्जन काफी तेजी से बढ़ा है। कार्बन डाई आक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान भी प्रभावित हो रहा है। हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग नामक शब्द हम सभी ने अवश्य ही सुना होगा। यह ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के बढ़ते तापमान का एक दूसरा कारक है। एक अन्य गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में एक

बड़ा कारक साबित हो रहा है। यह गैस सीधे ही वायुमंडल में घुल जाती है और ओजोन की परत में छिद्र बना देती है। गौरतलब है कि ओजोन गैस हमें सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश को हमतक सीधे पहुंचने से रोक देती है जिससे हम इसके हानिकारक प्रभाव से बच जाते हैं। बढ़ते तापमान के साथ ओजोन में बढ़ते छिद्र ने दुनिया के समस्त वैज्ञानिकों को हैरत व चिंता में डाल दिया। इस मामले पर एक संधि सभी देशों के मध्य की गई जिसे मोंट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 का नाम दिया गया। इस प्रोटोकॉल में ऐसे पदार्थों के उत्पादन में कटौती की बात कही गई है जो ओजोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने दुनिया को उसके पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रयास तो किए हैं परंतु ये प्रयास कितने कारगर होंगे यह तो इस प्रोटोकॉल को कार्यान्वित करने की मंशा पर ही निर्भर होगी।

पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए हमें समग्र और साझा प्रयास करने होंगे। आज वैश्विक मंच पर हर देश के महत्व की कसौटी उसका विकास दर है। अभी तक हमने जिस तीव्र विकास दर को पाया है, उसकी बड़ी भारी कीमत पर्यावरण के क्षय के रूप में अदा भी की है। अतः विकास और पर्यावरण के मध्य एक विलोम सा संबंध बन गया है। इसी कारण से कार्बन उत्सर्जन की कटौती या कार्बन क्रेडिट जैसे विषयों पर विकसित देशों और विकासशील देशों के मध्य टकराव देखने को मिलते हैं। एक तरफ विकासशील देशों पर विकसित देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन का आरोप लगाते हैं तो वहीं विकासशील ने विकसित देशों पर पहले ही तय सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर लेने का आरोप लगाते हैं। इस प्रकार के टकरावों से विश्व में पर्यावरण के संरक्षण में कुछ खास हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रयास तो साझा करने ही होंगे। विकसित देश विकासशील देशों को ऐसी तकनीक उपलब्ध कराएं जिससे कि कार्बनिक यौगिकों के कम उपयोग या उत्सर्जन के बावजूद उनके उत्पादन क्षमता, औद्योगिकीकरण या रोजगार पर प्रतिकूल असर ना पड़े। हमें समग्र प्रयास करने होंगे। जैव विविधता को संरक्षित करने के साथ-साथ, प्रदूषण को हर हाल में नियंत्रित करना होगा। वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा। जल- जंगल- जमीन को प्रदूषित या गलत तरीके से उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने होंगे तथा इनका कड़ाई से पालन करना होगा। अक्षय उर्जा जैसे कि सूर्य ताप, पवन उर्जा आदि का उपयोग अधिक से अधिक करना होगा। बच्चों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण का महत्व व इसके संरक्षण के महत्व को प्रमुखता से शामिल करना होगा। समाज में अन्य मुद्दों की ही भांति इसे भी गंभीरता के साथ उठाना होगा।

अतः पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। सरकार के द्वारा बताए गए तरीके से अपशिष्टों का निस्तारण करना, पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों पर अपनी निर्भरता कम करना, पौध या वृक्षारोपन करना, नदियों को अपने स्तर से प्रदूषित नहीं करना, इससे संबंधित नियमों-कानून का पूरी निष्ठा से पालन करना आदि ऐसे कार्य हैं जो हम अपने घर से ही कर सकते हैं। जब हम ऐसा करने लगेंगे तब ही समाज और उसके बाद देश और उसके बाद विश्व भी करने लगेगा। प्रकृति और पर्यावरण हमारे हैं और हम उनके। हम दोनों का अस्तित्व अन्योन्याश्रित है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

ऑचलिक प्रबंधक दिल्ली-1

APY- Not Just about Pension but an Exceptional Investment



Pulkit Roy

Pension has always been seen as cherry on the dish when it comes to employment. One of the big reasons that people aspire to get employment in Govt Services is because of the pension benefits. It is an important parameter that assures a person to lead a dignified life after his retirement, in other words, he does not have to be dependent on his children or anyone else for his financial needs when he retires from service. In a recent programme on retirement “Happy & Healthy living” conducted at STC Rohini. Hon’ble Executive Director Dr. Ram Jass Yadav have stressed upon the need of regular cash flow that a person should have after retirement. He said it will add up to the employee’s confidence level while dealing with family members and society.

In a country like India with a population of more than 130 billion, neither it was possible to accommodate every individual in Govt Sector so that they can be benefitted under Pension Schemes, nor the Govt can arrange for funds so required. So, with more than 410 million plus population working in unorganized sector, the requirement of a scheme that could deliver benefits of Pension was felt. An Individual who loses opportunity of regular income generation may feel depressed and unhappy. With depleting family connection and emerging nuclear family concepts, it has been observed that the one who loses income generation capacity, loses his credibility among family members and among his social circle.

Hence, Govt of India Launched NPS-Sawalambhan Scheme on 26.09.2010 which relaunched on 09.05.2015 with enhanced features and renamed as Atal Pension Yojna.

General Perceptions

The Scheme charts out list of premiums that an individual has to pay for desired pension amount ranging from Rs.1000/Month to Rs.5000/Month according to the age of such individual at the time of application. A person who is 18 years old has to pay a premium as low as Rs.42/- for a guaranteed pension payout of Rs.1000/- after he attains 60 years of age. Just Rs.1000/-, Doesn’t look lucrative? Let’s explore this scheme further. Rs.5000/- guaranteed against a premium of Rs.210/Month for 18-Year-old applicant. Even now, many would question the value of Rs.5000/- after say 30-40 Years. This point of view cannot be ignored but maybe there is another angle to look at it.



If we compare the increase in prices of daily needs of a family versus the increase in the average income, we may find that, purchasing power of Rs.100/- has declined a lot comparatively but still it manages to find a considerable space when it comes to our house hold needs. So, we may say that Rs.5000/- or even Rs.1000/- will have considerable space in our budgeting even after 30-40 Years. But is this



value fixed? Or there are chances of increase, Let's find out.

The Schemes is aimed at building a targeted Corpus which will be invested to buy annuity with some pension funds like SBI Pension fund etc. For Example, whether a person is applying in 18 years of age or 39 years of age. The premium is designed in such a way that it will lead to a targeted corpus. Rs.1.70 Lakhs for Rs.1000/Month Pension, Rs.3.40 Lakhs for Rs.2000/Month, Rs.5.10 Lakhs for Rs.3000/Month, Rs.6.80Lakhs for Rs.4000/Month and Rs.8.50 Lakhs for Rs.5000/Month payouts or pension. Even if this targeted corpus is not achieved, The Govt of India guarantees the payouts so promised at the time of enrollment.

Still does it sound appealing? Let's look at it from investment point of view.



India is a developing Economy, the Govt. Promotes Savings through different schemes out of which some are long term and some are short term. These schemes range from Public Provident Fund to Senior Citizen Savings Schemes. The Basis of attraction under these schemes is the interest rates and also tax benefits except in Senior Citizen Savings Schemes. It is kind of Borrowing that Govt takes from its citizen at interest rates more than what you get in other debt instruments like Bank Fixed Deposit etc. Now the thing to ponder is whether the global scenario is same? What about Banks in USA and European Countries where they have developed economy? The US Banks pay as low as 1.25% or so for deposits, if we take inflation into account. It can be assumed that rate of return is negligible. Likewise, Most of European Banks do not pay anything for keeping deposits. Instead, some of the economies charge their customer for parking their money in Banks. This trend indicates that a developed economy has meagre to negative rate of return for funds a person parks in some institution. Coming back home, if we compare the

FDR interest rates a Bank used to pay in 2013 versus today, we may find that there is a considerable decline to the tune of 3-4%. This means we may further expect that as soon as Indian Economy approaches towards a developed one, the ROI in Debt funds will come down. So, what we think of our investments that we have parked in such debt instruments.

Understanding APY as Investment

The Scheme promises a fixed payout according to premium paid. Let's say a person at whatsoever age opts for Rs.5000/ Month Pension. Means the scheme targets a corpus to be Rs.8.50 lakhs. Now there can be two conditions that can come, one is that corpus may become less than this target and another is it may surpass depending on market conditions. Let's assume that APY Fund Managers manages to build Rs.8.50 Lakh corpus for the given case when the applicant reaches 60 years of age or retirement age. Now, the rate of annuity that pension funds are presently offering is nearly 6%. Even if we calculate the amount of payout according to 6%, we land up with Rs.4229 per month as payout whereas APY guarantees a person for Rs.5000/- payout right from start of this scheme. A tabular presentation is also shown for better understanding:

Corpus (Amt in Lakhs)	Payout		Increased Return on Investment with APY	
	FDRs/Pension Funds Annuity @ 6% (Presently)	APY	Difference	Considering Subscriber lives till 70 Years of Age (=20*12* Difference)
8.50	4229	5000	771	185040
6.80	3383	4000	617	148080
5.10	2537	3000	463	111120
3.40	1692	2000	308	73920
1.70	846	1000	154	36960

APY subscriber have been given an option to Voluntarily Exit the Scheme, all the premiums paid by him will be refunded back to the source account. In case the subscriber to APY dies before turning sixty years of age, the spouse has an option to continue paying premiums and get pension after completion of Year to Maturity (as contracted by person died) or claim all the contribution paid by the subscriber back. If at all the spouse also dies, the nominee will receive full corpus accumulated. Chances of corpus to be more

than what is being targeted is also bright which can provide a nominee with additional corpus after death of subscriber. Considering that India will grow to be developed economy we may assume that the chances of Interest rates (or rate of return on debt investment) further going down cannot be ignored, that is another factor to consider this as an exceptional Investment. NPS Trust has recently celebrated crossing more than 3.3 crore subscriber up to August 2021 in which almost 70% market share is of Public Sector Banks.

Marketing and Challenges

The customer who walks into the Branch is more concerned about his job in hand and may have little time to understand all about APY as explained above. Many of the customers may not even understand the ROI theory. One of the main issues that I have come across is that it takes a lot of effort to make customer realize payouts. But we know that the same customer happily enrolls for an LIC policy which neither covers him for his required risk, nor the payout is more than 6%. The LIC is able to market their products in such a way that customer believes it to be the most beneficial investment. One thing that can be seen in LIC agents is the conviction that the product they are offering is unique and best.

We may be able to market APY Scheme in a better way if, we feel convinced at heart and sub conscious level that the scheme is actually worth subscription even to investment seekers like us.

To investors, it ensures best returns among all debt instruments along with affordable premiums which attracts benefits under 80C of Income Tax Act.

To the unorganized sector employee, it guarantees unmatched benefits that they can harvest at a verge of life which desires financial independence. It may not serve as the main source of such financial independence but can surely become a considerable ingredient. Be it from social security angle or from investment point of view, the APY is one scheme which always has something for you. It not only gives us opportunity to generate Non-Fund Income but also help create a connect with customers by making them realize the provisions required at certain age. The package of returns offered under Atal Pension Yojana collectively leads to an Individual's Social Security which by nature is at core of Public Sector Banking.

Faculty STC Rohini

FGM Office conducted a Meeting with Retired AGMs & above Executives of Tricity (Chandigarh, Mohali, Panchkula)



CUSTOMER MEET

A Customers Meet at Shimla was organised where Executive Director Shri Kollegal V Raghavendra felicitated the customers and also and also interacted with them.



बैंक के प्रधान कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन



Annexure- B

Integrity Pledge for Organizations

We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness.

We realize that as an Organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

We, therefore, pledge that:

- We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity;
- We shall not offer or accept bribes;
- We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness;
- We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business;
- We shall adopt a code of ethics for all our employees;
- We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties;
- We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities;
- We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large.



बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में ऑचलिक कार्यालय दिल्ली-I एवं दिल्ली-II के सम्मिलित प्रयासों से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का महा आयोजन





Naresh P. Tolani

VIGILANCE ANGLE

Vigilance Angle is the basic prospective and determination to start the investigation, means to ensure clean and prompt administrative actions towards achieving efficiency and effectiveness of the employees in particular.

Central Vigilance commission Act, 2003. Regulation 19 of 1982 Regulations framed there under makes it obligatory whenever there is a vigilance angle involved in disciplinary cases, consultation with CVC is important and also it is to be noted that absence of vigilance angle in various acts of omission and commission does not mean that the concerned official is not liable to face the consequences of his actions. All such lapses not attracting vigilance angle would, indeed, have to deal with appropriately as per the disciplinary procedure under the services rules.

Vigilance angle is obvious in the following acts:

- Demanding and / or accepting gratification other than legal remuneration in respect of an official act or for using his influence with any other official.
- Obtaining valuable thing, without consideration or with inadequate consideration from a person with whom he has or is likely to have official dealings or his subordinates have official dealings or where he can exert influence. 18 Vigilance Manual 2017 Chapter - I Vigilance Administration
- Obtaining for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by abusing his position as a public servant.
- Possession of assets disproportionate to his known sources of income.
- Cases of misappropriation, forgery or cheating or other similar criminal offences.
- Irregularities in opening of accounts leading to the creation of fictitious accounts;
- Recurrent instances of sanction of Overdrafts (ODs) in excess of discretionary powers / sanctioned limits without reporting;
- Frequent instances of accommodations granted to a party against norms e.g. discounting bills against bogus MTRs; purchase of bills when bills had earlier been returned unpaid; affording credits against un-cleared effects in the absence of limits and opening Letter of Credits (LCs) when previously opened LCs had devolved;
- Cases in which there is a reasonable ground to believe that a penal offence has been committed by the alleged official but the evidence forthcoming is not sufficient for prosecution in a court of law e.g. possession of disproportionate assets; Vigilance Manual 2017 193 Chapter - VIII Specific Issues Related to Public Sector Banks & Insurance Companies
- Misappropriation of Banks property, money or stores;



In the Banking parlance, the following actions would be perceived to have vigilance angle:

- Falsification of Bank's records;
- Disclosure of secret or confidential information even though it does not fall strictly within the scope of Bank's Secrecy issues;
- False claims on the Bank viz. TA claims, reimbursement claims, etc.;
- Failure to take necessary action to protect the interest of the Bank;
- Sacrificing/ignoring the interest of the Bank and causing loss to the Bank.

The following actions involving an employee would also come under the purview of vigilance angle, if he/she —

- has not acted in accordance with rules and his recommendations are not in the interest of the Bank;
- has failed to conduct himself in such a manner that his

decisions or recommendations do not appear to be objective and transparent and seem to be calculated to promote improper gains for himself or for anyone else;

- has acted in a manner to frustrate or undermine the policies of the Bank or decisions taken in the Bank's interest by the management;
- seems to have complied with unauthorised and unlawful oral instructions of his seniors without bringing them to the notice of the Competent Authority as per extant guidelines;
- has exceeded his discretionary powers and his actions do not appear justifiable or to serve Bank's interest;
- has abused or misused his official position to obtain benefit for himself or for another.

Deputy General Manager
HO Vigilance Department

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

PSB Salary PLUS Account
P - Privileged Account for L - Live Care and US - Universal Savings

Insurance Benefits

- Accidental / Permanent Total disability: ₹ 40 Lakhs (Claims for only one Accident or PTD will be covered)
- Air Accidental cover where ticket has been bought through Bank's debit card: ₹ 120 Lakhs
- Child Education benefit of (i) ₹ 6 Lakhs (for child between 12-22 yrs) Additional benefit (ii) ₹ 6 Lakhs in case of Girl Child (Wherever accidental death claim is admissible * Max two children)
- Ambulance Charges : Max ₹ 3000 per case
- Terrorism Naxalite/Militant Activities to be covered: As per Sum Assured
- Death due to Animal Bite/Insect Bite/Snake Bite to be covered: As per Sum Assured

Service Benefits

- Two Months Net Salary OD Facility
- 25% Locker Charges discount for Small Lockers (if available)
- Annual Debit Card Charge Waiver
- SMS Charges Waiver

For further details, please contact our nearest Branch or Visit us at: www.punjabandsindbank.co.in

1800 419 8300 (Toll Free)

Follow us @PSBIndOfficial

NEO BANKS: ARRIVAL OF “CHALLENGER BANKS”



T.K Nazimudeen

“It is not the Customer’s job to know what they want.”

: Steve Jobs

Technology and internet speed has stirred up many business models and the banking sector is not an exception. New players in the banking sector attracting customers to digital services with convenience and seamlessness. In these days new fintech models are emerging and neo banking is one of them. In India also fintech companies are growing in considerable pace and Neo banks have changed our banking landscape with innovative way they do business.

What is a Neo bank?

Neo banks are virtual fintech banks. They are online banking channels without any physical branches. Neo banking provides complete digital banking experience to their customers through customised online applications. Neo banks also referred to as “challenger banks,” .What make them “challenger banks” is they are challenging the traditional banking models with their custom made technology that offers apps, platforms and other innovations to streamline mobile and online banking. Neo banks are customer-oriented and provide personalized services. They are custom made fintech firms that offer apps, software and other technologies to streamline mobile and online banking. These fintechs generally specialize in particular financial products, like payment platforms, digital savings accounts, peer to peer lending and investment interface. They also tend to be more nimble and vibrant than their megabank counterparts, even though many of them partner with such institutions.

How does a Neo banks work?

Armed with internet based customer experience, neo banks provide solutions in many ways that traditional banks cannot. Neo bank’s service delivery model is cheaper, faster and they can integrate the entire financial portfolio



in one single platform. Along with the explosion of mobile technology there is a massive drift in the financial industry. Bank customers are embracing digital means moving away from physical cash. At the same time chat bots and AI are making it possible to analyse customer patterns, credit history, and other data to create realistic data models for recommending financial services based on their lifestyle choices. The integration of technology and banking services has changed the banking industry’s service delivery model that is more customer-oriented. In a way, Neo banks are providing a fluidity that traditional banks can’t.

How does a Neo bank differ from a traditional bank?

Neo banks are very different from traditional banks in every aspect and their business. A business model on which a neo bank works is altogether different from a traditional banks. Since they are fully digital and technology plays a vital role in their working model. Neo banks mostly work on the decision-making model which is driven by customer data-based decisions. They collect and analyse customer data, understand the patterns, try to calculate how their

customers behave, and then create predictions/results. Neo banks are customer-centric and offer personalized services to customers, which differentiates them from traditional banks. Neo bank platforms enable users to validate their service offerings in real time through online channels. These platforms also eliminate the need for human interference, thereby reducing transaction errors. Additionally, benefits offered by neo banking, such as fast servicing, healthy interest rates, and cost-effective banking within a single platform.

In addition to basic saving account features, these neo banks offers innovative service like

1. Track customer's utility bills and credit card payments and provide one click payment option.
2. Providing cash rewards and brand discounts and automatic service upgradation.
3. Money wallets with flexible interest benefits and with P2P lending option.
4. Monitored payments for teens/kids/special customers under the supervision of their parents /guardian with digital cards which is secured.
5. Collection of B2B payments from clients, make pay-outs to vendors and payroll service Small business and traders with nominal monthly fee.
6. Multi-currency accounts, payments, money transfers, expenses roll, instant cards, crypto, wallets, budgets & analytics,

Global scenario of Neo Banks

The global neo banking market size was valued at USD 34.77 billion in 2020. It is expected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 47.7% from 2021 to 2028 and expected to touch USD 600 billion in next 07 years. The increasing demand for customer convenience in the banking sector is expected to drive the growth of the market. Substantial growth potential for neo banks is also driven by its low-cost model for end-users with very low or no monthly fees for financial services such as withdrawals, deposits, and balance maintenance.

Source: Techcrunch.com

Reserve Bank of India on Neo Banking's future

As of now in India Neo banks do not have a bank license of their own but rely on other bank partners to offer bank licensed services as under Indian regulatory regime does not allow for the granting of virtual banking licenses. RBI, through its 2015 Master Circular on "Mobile Banking Transactions in India – Operative Guidelines for Banks", has mandated the requirement for digital banking service providers to have some physical presence. At present in India neo-banks can provide banking related services only through outsourcing their banking responsibilities to licensed banking institutions and non-banking financial companies.

In addition to the above guidelines, neo-banks are also obligated to comply with data protection laws since they facilitate a number of services between the consumer and the banking institutions by providing an online platform. The Indian data privacy regime is set out in the IT Act and the Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 (SPDI Rules). Neo-banks, for a long time, have not been operating to their full potential. RBI in 2019, had introduced a new regulatory sandbox for testing new financial technologies. Similar regulatory sandbox should be introduced for neo-banks considering their potential to accelerate financial inclusion of the masses.

What is at stake for Indian banking sector

In India, Neo banks are already on the rise and they are disrupting traditional banking models. Becoming the future of banking, their popularity has increased in a relatively short span of time. Over the last 3 years, India has seen the





rise of neobanks with 811 by Kotak, Yono by SBI, RazorpayX, Open, NiYo, and more. And, these neobanks have been successfully helping SMEs, large enterprises, and the gig economy with billing, cash flow management, disbursements, vendor management, and so much more.

Neo banks can play a key role in making India digital and providing customers with detailed, analysis-oriented all in one kind of banking experience. Our traditional banks can tie up with Neo banks. Neo bank will act as a catalyst to the existing banking system and will enlarge the reach of the banks. They have the agility as they would have a leaner structure for being technologically driven. Though they will have an inability to lend beyond a certain quantum, they can increase capital by tie up with banks. The turnaround time of providing service would enable seamless service at a lower cost. While Neo banks are primarily fintech companies that have their own limitations but they can complement the banking industry. Financial inclusion would be most cost-effective and faster through Neo banks.

There are over 42.50 million small and medium-sized businesses throughout India, constituting nearly 95% of the total industrial units in the country. But, only 47% of these businesses have been able to access tools for payments, disbursements, and other vital processes. Furthermore, about 23% of SMEs use ERP software and CRMs. This means, there's a huge market opportunity for neobanks and fintechs in coming years.

India has over 15 million contract workers and freelancers, who actively boost the growth of start-ups. And just like SMEs, only about 67% of the gig economy has access

to innovative tech that helps with money management. Neobanks can help the gig economy by enabling independent workers with customer management and banking services. Neo banking can work as an extension of measures undertaken to solve the challenges of financial inclusion and bundling banking services with other financial services—for example, services like opening of bank accounts for immigrants, facilitated through new onboarding procedures not based on traditional documentation of identification. With narrow targets initially, neobanks could expand by adding more functionalities and services over time

Globally, India has the 2nd largest base of internet subscribers, smartphones, and social media user base. With over 600mn digitally active customers, India offers a large market for digital banking services. This growth has been enabled by India's public digital infrastructure and other regulations and policies.

This leaves the neo-banks with cross-selling of financial products (wealth management, insurance, community-led discounts, stock market investments, etc.) and account opening commissions from banks as the primary source of income. To survive long term and be competitive Indian banks should either develop a fintech platform internally or they should tie up with the Neo banks to maintain their technological edge to keep the market share intact.

How to compete with these Challenger Banks

Traditional brick and mortar banks want to compete with the Neo Banks have only one option that is to stay relevant as consumer preferences shift to digital banking models. It is a huge challenge to the traditional banks to refresh their IT infrastructure. Moulding the workforce to tech savvy is also a tough task. To begin a journey to digital transformation, institutions have to develop a detailed strategy to change their distribution model, revise and enhance value offers, as well as develop end-to-end customer-centric processes that can result in growth and customer satisfaction. Traditional banks should keep in mind while defining their digital road map.

a) Even though traditional banks have multi-channel



banking (ATM, Online banking, branch, telebanking, call centre etc.), they are unable to provide a consistent user experience across these channels. These banking channels work in silo and have independent data base, technical and functional architecture that fail to coordinate user-friendly service due to scattered customer data base.

- b) In "Anytime, Anywhere" business model, personalization has become the inevitable force to attract the new generation of customers who want more customized products and services that tailored to their actual needs. The tech-savvy customers want their banks to respond to them through their preferred channels.
- c) In the first step, traditional banks should migrate to Omni Channel Banking in which customer have agile to move between the channels to select his option of service. Here he can initiate a transaction in one channel and view and complete in any other channel.
- d) Since different channels within Omni Channel uses same customer data that work on common functional logic for selection of specified banking service by customer. This common data base and user preference can help banks to build a valuable database about the customer.
- e) Customer database is a very valuable resource for banks that because with advanced analytics techniques such as predictive and prescriptive analytics enable precise

modelling of customer behaviour. These in turn drive increased cross-selling and up-selling opportunities, pricing optimization, and targeted offerings. Predictive Analytics helps unlock opportunities that provide past buying behaviour, demographics, and information from social media along with CRM data, Predictive Analytics help improve customer engagement,

experience, and loyalty.

- f) To be at par with nimble fintech players and Neo Banks, traditional banks need to transform their multiple silo-end channels and legacy applications into a harnessed Omni platform that provide a customer interface simple to use and always available. A robust, consolidated platform that can make sure that the right data is made available at the right time with harmoniously is essential for a competitive Omni-channel.

Bottom Line

Neo banks or challenger banks are expanding their customer base with their agile and custom made digital applications. These new-age Fin-Techs and neo banking entrants proving that they are unicorns with cutting edge technology and innovation. Reserve bank of India is keeping close watch to manage their vital impediments in terms of regulation and compliance, data and cyber security, seamless API integration and expansion of products and services. But the growth of Neo banks are in fast pace as consumers overwhelmed with speed and convenience of their service delivery. These challenger banks holding huge data of the customers. Traditional banks should catch up with them armed with more technology driven business models. And of course innovation is the driver in modern business. As said by Steve jobs "It is not the Customer's job to know what they want".

Asst. Gen. Manager
HO Inspection

REVIEW MEETING

बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री कोल्लेगल वी. राघवेन्द्र जी ने दिनांक 09.12.2021 को अंचल लुधियाना एवं जालंधर में पदस्थ वरिष्ठ प्रबंधकों एवं उससे ऊपर के स्केल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर क्षेत्रीय महा प्रबंधक श्री प्रवीण कुमार मोंगिया के साथ अंचल लुधियाना के आंचलिक प्रबंधक श्री अशनी कुमार एवं अंचल जालंधर के आंचलिक प्रबंधक श्री राजेश कुमार मल्होत्रा जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक महोदय ने समीक्षा के साथ-साथ प्रभावशाली तरीके से बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शाखा प्रबंधकों को कार्यकारी निदेशक महोदय ने सम्मानित भी किया।



BRANCH MANAGERS REVIEW MEETING

Zone Delhi-1 Review Meeting of Branch Managers by Executive Director Sh. Kollegal V Raghvendra



Branch Managers Review Meeting was conducted in Chennai in the presence of our Respected General Manager Mr. Kamesh Sethi. Performing branches were felicitated by respected GM Sir. The meeting was very interactive and very productive for all the participants who were sensitised and motivated by Respected GM Sir to achieve the desired results. All the participants promised that they will overcome their shortcomings and achieve the allocated targets wholeheartedly.



बैंक के प्रधान कार्यालय में सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु न



गणक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर कीर्तन का आयोजन



क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम

कानपुर में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश खन्ना, वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, ने बैंक के स्टाल पर जानकारी प्राप्त करते हुए।



Performance for the quarter ended 2021

**Punjab and Sind Bank posts record
Net Profit of Rs.301 Cr against a Net Loss of
Rs.2376 Cr (Y-o-Y)**

- ◆ **Q3 FY – 2022 Highlights (Y-o-Y)**
- ◆ **Operating Profit zooms by 153.44% to Rs.332 Cr.**
- ◆ **Net Interest Income grew by 23.05%.**
- ◆ **Cost of Deposits (COD) at 4.24%, improved by 73 bps.**
- ◆ **Total deposits grew by 10.87% & stood at Rs.100351 Cr.**
- ◆ **Gross Advances grew by 3.26%.**
- ◆ **Retail advances grew by 12.15%.**
- ◆ **Net NPA ratio stood at 3.01%.**

PERFORMANCE – DECEMBER 2021

Parameter	For the Quarter			Y-o-Y	Q-o-Q
	Dec'20	Sept'21	Dec'21	(%)	(%)
Total Business	155115	169484	167061	7.70	(1.43)
Total Deposits	90509	101910	100351	10.87	(1.53)
Saving Deposits	26052	27235	29069	11.58	6.73
Current Deposits	3270	3585	3680	12.54	2.65
CASA Deposits	29322	30820	32749	11.69	6.26
CASA % to Total Deposits	32.40	30.24	32.63	23 bps	239 bps
Retail Term Deposits	43223	45279	45536	5.35	0.57
Bulk Deposits (incl CDs)	17964	25811	22066	22.83	(14.51)
Gross Advances	64606	67574	66710	3.26	(1.28)
Retail Advances	9543	10198	10702	12.15	4.94
Agriculture Advances	9945	10308	10296	3.53	(0.12)
MSME Advances	11648	11738	12121	4.06	3.26
% of RAM Advances to Gross Advances	48.19	47.72	49.65	146 bps	193 bps
Corporate Advances	33470	35330	33591	0.36	(4.92)
Gross Investment	30849	37553	37651	22.05	0.26
Operating Profit	131	301	332	153.44	10.30
Net Profit / (loss)	(2376)	218	301	112.67	38.07
Non Interest Income	211	256	171	(18.96)	(33.20)
Net Interest Margin (%)	2.86	2.60	3.17	31 bps	57 bps
Cost of Deposits (%)	4.97	4.30	4.24	(73) bps	(6) bps
Yield on Advances (%)	7.92	6.92	7.69	(23) bps	77 bps
Cost to Income Ratio (%)	84.11	65.57	64.20	(1991) bps	(137) bps
Return on Assets (%)	(8.90)	0.72	0.98	988 bps	26 bps
Earnings Per Share (Rs)	(135.54)	2.15	2.97	102.19	38.14
Gross NPA	8490	9823	9636	13.50	(1.90)
Gross NPA%	13.14	14.54	14.44	130 bps	(10) bps
Net NPA	1638	2288	1773	8.24	(22.51)
Net NPA%	2.84	3.81	3.01	17 bps	(80) bps
Provision Coverage Ratio (%)	87.99	84.44	87.77	(22) bps	333 bps
CET-1 (%)	11.45	12.25	12.34	89 bps	9 bps
CRAR (%)	16.39	17.92	17.82	143 bps	(10) bps

ZONE WISE PERFORMANCE

Zone	CASA Deposits (ex Overdue FDRs)			Deposits			Total Advances			Retail Credit			Agriculture Credit			MSME Credit		
	Mar' 21	Dec' 21	Target Mar' 22	Mar' 21	Dec' 21	Target Mar' 22	Mar' 21	Dec' 21	Target Mar' 22	Mar' 21	Dec' 21	Target Mar' 22	Mar' 21	Dec' 21	Target Mar' 22	Mar' 21	Dec' 21	Target Mar' 22
Amritsar	2056	2260	2465	5203	5174	5860	1766	1797	2500	834	837	1020	844	858	1100	373	360	540
Bareilly	1071	1056	1300	1843	1699	2410	1627	1686	2200	594	666	710	1054	1060	1295	320	352	430
Bhatinda	686	842	910	1464	1646	2025	1354	1351	1700	402	439	500	982	938	1235	171	171	250
Bhopal	810	808	1050	2548	2363	3110	1241	1270	1800	792	746	925	187	169	245	642	598	930
Chennai	257	232	510	1258	1263	1650	1987	2296	2550	843	869	1020	8	8	60	436	436	590
DRB of FGMO	3413	3723	4070	9788	10875	11310	3816	4058	4800	1733	1946	2100	1151	1084	1500	1086	1082	1480
Dehradun	1178	1229	1365	2547	2551	3000	1050	1092	1275	569	640	670	410	392	485	291	317	365
Delhi - I	1789	1946	2110	11167	10896	12400	10470	9440	12250	1054	1085	1240	31	36	105	1039	1238	1365
Delhi - II	2661	2640	3060	7822	7821	8700	1727	1726	2700	1062	1039	1280	125	67	225	883	810	1290
Faridkot	1299	1476	1610	2812	3009	3665	1661	1637	2100	555	582	650	1233	1152	1435	214	234	350
Gandhinagar	151	159	315	624	760	1020	1002	923	1300	428	457	530	46	54	65	242	267	310
Gurdaspur	1396	1522	1700	3087	3257	3925	1229	1255	1700	528	541	645	636	638	800	290	293	470
Gurugram	844	907	1075	2079	2078	2600	1209	1254	1800	944	985	1140	185	190	250	429	444	600
Guwahati	634	622	800	1286	1204	1650	279	304	325	227	242	260	9	8	30	126	143	150
Hoshiarpur	1284	1383	1495	3010	3193	3700	759	784	1000	253	297	340	495	474	650	99	128	145
Jaipur	618	598	815	2046	1784	2450	1897	2203	2450	916	973	1070	679	695	815	563	575	765
Jalandhar	2115	2321	2485	5480	5768	6500	1127	1227	1550	702	795	850	314	324	400	394	417	575
Kolkata	1228	1317	1525	3880	4103	4510	4217	4211	5400	1241	1289	1510	156	121	225	841	879	1175
Lucknow	1418	1541	1740	3684	3563	4400	1866	2051	2500	1222	1302	1490	212	216	260	733	797	940
Ludhiana	1650	1803	1990	3916	4073	4740	2163	2219	2625	855	911	1040	606	584	750	722	731	960
Mumbai	605	784	1030	12420	13771	13125	9498	7896	11300	744	746	945	38	33	90	413	708	630
Noida	1386	1344	1675	3015	2996	3500	985	980	1375	793	795	975	161	152	200	265	265	400
Patiala	1272	1350	1565	3292	3462	3950	1826	1849	2300	643	692	800	1042	1005	1225	289	275	410
Vijayawada	371	456	540	1794	3051	2300	7840	8130	9300	635	711	790	33	42	55	283	331	380
SAMVERT	0	0	0	0	0	0	5216	5068	0	14	14	0	0	0	0	353	303	0
Total	30191	32318	37200	96108	100361	112500	67811	66708	78800	18579	19601	22500	10638	10298	13500	11497	12152	15500

FINANCIAL AWARENESS CAMP

Financial Awareness Camp was organised by Reserve Bank of India at BABA BAKALA SAHIB. The executive from RBI Chandigarh appreciated Staff of branch Baba Bakala Sahib for contribution. They remarked that the programme is thier beyond expectations.



MARKETING CAMPAIGN



पुरी, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर



कुरुक्षेत्र में गीता जयंती पर



ऑचलिक कार्यालय लखनऊ



हुगली में शिपयार्ड



ऑचलिक कार्यालय कोलकाता

Important Circulars issued by different department

Circulars No.	Circulars Date	Particulars
Name of Department: Account & Audit		
964/2021-22	05.10.2021	Amendment in GST provision w.r.t. filing of GSTR-1 and exemption from Aadhar authentication
1011/2021-22	21.10.2021	Special provision for deduction of tax at source in case of interest payments to Scheduled Tribes residing in specified area (W.E.F. 17.09.2021) Download: Annexure
1010/2021-22	21.10.2021	Exemption from the filing of return by an individual whose age is 75 years or above (Section 194P) Download: Annexure
1037/2021-22	02.11.2021	Guideline on GSTR-2B statement
1052/2021-22	09.12.2021	Clarification w.r.t. Section 194O & 194 Q of Income Tax Act, 1961
1185/2021-22	27.12.2021	Master Circular on Limited Review December 2021 Download: Annexure
1190/2021-22	28.12.2021	Closing of Trading Window in terms of Punjab & Sind Bank Code of Conduct to Regulate, Monitor and Reporting Trading by Insiders
1191/2021-22	22.12.2021	Perquisite valuation for FY 2021-22
Name of Department: Foreign Exchange		
977/2239/40/2021	11.10.2021	Foreign Contribution (Regulation) Act,2010- Receipt of Foreign Contribution by Individual/NGOs/Organizations from Foreign Donor Agencies
984/2240/41/2021	13.10.2021	Exim Bank's Government Of India Supported Line of Credit (LoC) Download: Annexure I, Annexure II
1025/2021-22	29.10.2021	CHANGE OF NOTIONAL RATES FOR FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS
1028/2021-22	30.10.2021	Foreign Contribution (Regulation) Act,2010- Receipt of Foreign Contribution by Individual/NGOs/Organizations from Foreign Donor Agencies
1056/2021-22	10.11.2021	Interest Rate on Foreign Currency(Non Resident) A/C Banks Scheme-FCNR(B)
1057/2021-22	10.11.2021	Interest Rates on Resident Foreign Currency (RFC) Deposit Accounts
1075/2021-22	16.11.2021	Foreign Contribution (Regulation) Act,2010- Receipt of Foreign Contribution by Individual/NGOs/Organizations from Foreign Donor Agencies
1078/2021-22	18.11.2021	Foreign Contribution (Regulation) Act,2010- Receipt of Foreign Contribution by Individual/NGOs/Organizations from Foreign Donor Agencies
1107/2021-22	29.11.2021	Interest Rates Foreign Currency Non Resident account FCNR(B)
1114/2021-22	30.11.2021	Exim Bank's Government of India supported Line of Credit (LOC) of USD 10.40 million to the Government of the Kingdom of Eswatini (Swaziland)
1121/2021-22	30.11.2021	CHANGE OF NOTIONAL RATES FOR FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS
1126/2021-22	02.12.2021	NRI Deposit Mobilisation Campaign from 01.12.2021 to 15.01.2021 Download Annexure-1 , Annexure 2
1139/2021-22	07.12.2021	Foreign Contribution (Regulation) Act,2010- Receipt of Foreign Contribution by Individual/NGOs/Organizations from Foreign Donor Agencies
1166/2021-22	18.12.2021	Regarding Foreign Donors/Entities under Prior Permission Mode/Prior Reference Category
1172/2021-22	21.12.2021	Execution of Fallback clause in LIBOR linked Loans/Financial Contracts
1181/2021-22	22.12.2021	External Commercial Borrowings (ECB) and Trade Credits (TC) Policy- Changes due to LIBOR transition Download: Annexure
1182/2021-22	22.12.2021	Introduction of Legal Entity Identifier for Cross-border Transactions Download: Annexure
1192/2021-22	29.12.2021	Opening of accounts by individuals entities of Pakistan and Bangladesh nationality
1205/2021-22	31.12.2021	Revision in Interest Rates on Export Credit in Foreign Currency and Foreign Currency Denominated Loan consequent upon LIBOR Cessation
1207/2021-22	31.12.2021	CHANGE OF NOTIONAL RATES FOR FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS
Name of Department: Fraud Monitoring		
967/2021-22	06.10.2021	Cases Of Frauds/Attempted Frauds/Third Party Entities involved in Frauds (Sharing of Information) Download: Annexure
968/2021-22	07.10.2021	Fraud in Borrowal Account Amounting Rs.8.98 Crore
993/2021-22	14.10.2021	Fraud of Rs.1.90 Crore in 5 Housing Loan Accounts and 2 Others
1044/2021-22	09.11.2021	Cases Of Frauds/Attempted Frauds/Third Party Entities involved in Frauds (Sharing of Information) Download: Annexure
1120/2021-22	30.11.2021	Frauds/Cybercrimes and their modus operandi and preventive measures
1101/2021-22	10.11.2021	Fraud of Rs.63 Crore committed by branch officials
1120//2021-22	30.11.2021	Fraud of Rs.18 Crore in an ODP Account

of Head Office (01/10/2021 to 31/12/2021)

Circulars No.	Circulars Date	Particulars
1130/2021-22	04.12.2021	Fraud of Rs.4.50 Lakh in 1 KCC Loan Account
1131/2021-22	04.12.2021	Fraud of Rs.5.73 Lakh in 2 Vehicle Loan Accounts
Name of Department: General Administration		
1031/2021-22	02.11.2021	CHANGE OF ADDRESS OF SAGAR BRANCH
1042/2021-22	06.11.2021	CHANGE OF ADDRESS OF BALASORE BRANCH
1193/2021-22	28.12.2021	Change of Name & Address of Branch
Name of Department: Information Technology		
975/2021-22	08.10.2021	Revised Guidelines for Adoption of Integrity Pact in Procurements as per CVC: Names,Roles and Duties of IEM
1127/2021-22	03.12.2021	Vendor For Procurement of JAWS Screen Reading Software
1165/2021-22	16.12.2021	Rationalization of Financial (capital and Revenue Expenditure) powers related to Computerization
Name of Department: Inspection		
1189/2021-22	31.12.2021	Launching of Staff Accountability Portal (SAP) Download: Job card
Name of Department: Provident Fund		
985/114/2021	13.10.2021	Modification in guidelines for IBA's Group Medical Insurance Scheme 2021-22 for Bank Retirees and their Spouse
1050/115/2021	06.11.2021	Extended window for inclusion of left out retirees / surviving Spouse to join IBA's Group Medical Insurance Policy 2021-22
1082/116/2021	18.11.2021	Revision of Family pension and Enhancement of Employer's contribution under NPS as per Bipartite Settlement and Joint Note dated 11.11.2020
1140/117/2021	07.12.2021	Release of Stagnation increment notionally for the purpose of Pension under the 10th Bipartite settlement / Joint note
Name of Department: Planing and Development		
951/2021-22	25.10.2021	Revision of Benefits under Salary PLUS Account- UDAAN Scheme
1014/2021-22	25.10.2021	New Special Fixed Deposit Scheme: "PSB Sanchay TD Scheme for Salary Account Holders- Udaan Scheme"
1026/2021-22	30.10.2021	Inclusion of Additional Facilities to Existing Doorstep Banking (DSB) Services through Universal Touch Points (UTP) Mechanism Download: Annexure-I, Annexure-II, Annexure-III, Annexure-IV
1027/2021-22	30.10.2021	Doorstep Banking Nayi Shuruat Campaign from 01.11.2021 to 30.11.2021
1038/2021-22	03.11.2021	SUBMISSION OF ANNUAL LIFE CERTIFICATE BY OUR PENSIONER @ FREE OF COST THROUGH DOORSTEP BANKING SERVICE-UTP (PSB ALLIANCE DSB) IN 100 DSB CENTRE)
1084/2021-22	22.11.2021	RBI imposes monetary penalty on RBL Bank Limited
1085/2021-22	22.11.2021	Inclusion of "Paytm Payments Bank Limited" in the second schedule of the Reserve Bank Of India Act, 1934
1086/2021-22	22.11.2021	Seven NBFCs surrender their Certificate of Registration to RBI
1087/2021-22	22.11.2021	RBI Cancels Certificate of Registration of Six NBFC's
1125/2021-22	01.12.2021	Cancellation of License of Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd. on its transaction to Shivalik Small Finance Bank Ltd
1142/2021-22	10.12.2021	Revision of Benefits Under Salary PLUS Account- UDAAN Scheme Download: Annexure-I,Annexure-II,Annexure-III
1163/2021-22	15.12.2021	Revised Banking Hours for Jabalpur District (MP) Branches
1169/2021-22	20.12.2021	The Reserve Bank- Integrated Ombudsman Scheme 2021 Download: Annexure
1180/2021-22	21.12.2021	Policy on Safe Deposit Locker Facility / Safe Custody Article provided by the Bank

PRECAUTIONARY MEASURES FOR DISCIPLINARY ACTIONS



Mini Ren Kumar Gupta

Human Resources occupy the topmost position amongst all the resources that an Organization requires to survive and succeed. Banks are financial institutions that require financial resources to run their business but as rightly said by someone, “Financial resources may be the lifeblood of a company, but Human Resources are the brains.” It is said that all other resources are futile in the absence of Human Resources, whereas, Human Resources hold the capability to procure and produce all other resources when none are available readily. Therefore effective management and development of Human Resources is the key to successful running of a business and organization.



official who committed the lapses, so that in future, he will conduct himself in a more responsible fashion and to convey a message to the rest of the officials in the organization that they should not conduct themselves in a way detrimental to the interests of the Bank as otherwise they also might have to suffer similar unpleasant punishment.

Why Disciplinary Action? :-

Human Resources (employees) in an organization are expected to perform as per certain laid down standards and maintain conduct as required by rules of the organization which is called Discipline. Whenever, the expected performance is not met or the conduct is not maintained by any employee, it becomes imperative upon the Management to take immediate corrective action for promotion and maintenance of employee discipline as the same is essential for smooth functioning of an organization. One of such corrective action so taken to maintain employee discipline is called Disciplinary Action. Disciplinary Action is one of the control functions of Human Resource Management / Development. The objective of Disciplinary Action is to correct the employee, to instill a sense of guilt and resultant repentance on the part of the

What are Rules, Regulations & Guidelines followed by our Bank for Disciplinary Action?

In our Bank, Disciplinary Action Procedure to be followed in case of Officers is laid down in Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1981 whereas in case of Award Staff (Workmen) the procedure is laid down in Bank's Staff Circulatory Letter No. 2268 dated 25.07.2002 (Memorandum of Settlement on Disciplinary Action and Procedure thereof for workmen signed on 10th April, 2002 between Indian Banks' Association and Workmen Unions) which was amended vide HO HRD (DAC) Circulatory Letter dated 15365 dated 14.06.2021 as per Memorandum of Settlement signed between Indian Banks' Association and Workmen Unions on 11th November, 2020.

Disciplinary Authorities in case of Officers were amended vide Staff Circular No. 2638 Dated 31.12.2002 and in case

of Award Staff (Workmen) Disciplinary Authorities were empowered vide HO HRD (DAC) Circular No. 805/2021-22 dated 12.08.2021 (Deptt Ref. No. 3167).

Apart from the above, Principles of Natural Justice, Rules, Regulations & Guidelines issued by the Govt. of India, CVC & IBA are also duly adhered to while dealing with Disciplinary Action Cases.

What Precautionary Measures should be taken by the Disciplinary Authorities / Controllers while dealing with Disciplinary Action Cases ?

Attempt is made here to discuss only those actions which are generally not given importance while dealing with Disciplinary Action cases which renders the whole Disciplinary Action Procedure and violation of natural justice to Charge Sheeted Officials / Employees (CSOs/ CSEs).

Though it is not possible to prepare an exhaustive list of discrepancies / irregularities / inconsistencies to be avoided by the Disciplinary Authorities while dealing with the Disciplinary Action Cases, an effort is being made to mention certain impactful ones and the same are given hereunder :-

At Show Cause Stage :-

1. Allegations should be properly drafted and Irregularities / lapses reported by the Fact Finding Officer (FFO) should not be reproduced without framing the allegation. The allegations should be in such a form that explains as to how the accountable official has committed the irregularity or omitted something that the employee was required to do. The allegations may be refined by specifying the Guidelines, Circulars, Rules & Regulations violated by the employee.
2. Sometimes several irregularities / lapses are reported by the FFOs which do not actually exist at the time of issuing of Show Cause Notice to the Official / Employee. Sometimes FFOs do not report very significant irregularities / lapses. Documents should be scrutinized to find out such lapses / irregularities and these should invariably be included in the Show Cause Notice, Explanation Called letter or Comments Called letter. However, care should be taken to include only those lapses which either resulted in turning of account to

NPA category or recovery action are being hampered or borrowers have been accommodated unauthorizedly.

At Charge Sheet Stage:-

3. Charge sheet should be specific and contain all the necessary, particulars such as the time date and place of misconduct. Instruction given under point No.1 above w.r.t drafting of allegations should be adhered to while framing the charge sheet.
4. The Charge should not contain any expression that the Disciplinary Authority is prejudiced against the CSO/ CSE or under guidance / pressure of Higher Authorities.
5. DA should ensure that the Charge Sheet contains all the essential elements.
6. The DA should ensure that the Charge Sheet is served upon the employee and proof of service is on record.
7. Supporting documents to the allegation must be provided to the CSO/CSE vide annexures to the Charge Sheet.
8. Ex-parte action, if any, should be initiated after giving the CSO/CSE reasonable time and opportunity to submit his reply.

At the Inquiry Stage :-

9. In case of officers no order imposing any of the major penalties shall be made except after an inquiry is held in accordance with Regulation 6 of Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1981. Whereas in case of Award Staff (Workmen) Inquiry shall be held in both the cases i.e Gross Misconduct or Minor Misconduct.
10. DA should ensure that all the necessary documents required for the Inquiry are available to the PO and IA/ IO.
11. DA's should adequately educate the Inquiring Authority / Officer (IA/IO) and Presenting Officer (PO) regarding the procedure of conducting Inquiry Proceedings.
12. As career of the Charge Sheeted officials are at stake due to the Disciplinary Proceedings, Inquiry Authority should be well known to the process of Inquiry Proceedings and his findings should be clear and specific to every

allegations/charge so that no innocent become victim of injudicious findings of the Inquiring Authority. The Inquiring Authority must refer the detailed procedure of holding an Inquiry in case of Officer's as given in Regulation 6 of Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1981 and in case of Award Staff (Workmen) the procedure as given in clause 10 & 12 of Bank's Staff Circulatory Letter No. 2268 dated 25.07.2002 (Memorandum of Settlement on Disciplinary Action and Procedure thereof for workmen signed on 10th April, 2002 between Indian Banks' Association and Workmen Unions). Vigilance Manual of the Bank can also be referred for proper guidance and to do justice with his own role as an Inquiring Authority.

13. IA/IO should ensure that Inquiry Proceedings are recorded in the Inquiry Register along with signatures of CSO, DR (Defence Representative), PO and IO/IA.
14. IA/IO should ensure that documents produced by both the parties of Inquiry i.e PO and CSO/DR are properly marked. Documents produced by PO are called Management Exhibits and marked as MEX-1, MEX-2 ... and so on where as documents produced by CSO/DR are called Defence Exhibits and marked as DEX-1, DEX-2.....and so on. MEXs & DEXs should be referred by the PO & IA/IO in their brief and findings respectively.
15. IA/IO should decide the relevancy of each document sought by the PO and CSO/DR. IA/IO should ensure that all the relevant documents are available to the PO and CSO/DR within reasonable time.
16. IA/IO should ensure that Inquiry Hearings are conducted timely, adjournments are not taken by either of the parties on flimsy grounds and Inquiry Proceedings are completed within the stipulated time.
17. IA/IO should ensure that equal opportunity is given to both the parties of Inquiry viz., the PO and CSO/CSE / defence for production of Witnesses & Evidences. IA/IO should ensure that equal opportunity of (a) Examination in chief (b) cross examination and (c) re-examination is given to both the parties of Inquiry.
18. PO's duty is to prove the charges if not beyond doubt at least on the basis of preponderance of probability by leading oral and documentary evidence (direct or

circumstantial) and by drawing logical inference there from.

19. PO should make sincere efforts to produce his documents, evidences and witnesses in support of allegation. Merely repeating the allegation by the PO should not be accepted by the IA/IO. The PO must give proper reasoning and explanation in support of each allegation with supporting documents.
20. Many a times it is noted that the IA/IO submits his findings without obtaining PO brief & CSO/CSE brief. Please note that on completion of inquiry hearings, PO must submit his written brief to the IA who shall forward a copy of the same to CSO/ CSE to submit his/ her brief to the IA/IO.
21. Based on the briefs of the PO and CSO/CSE and witnesses evidences submitted during inquiry proceedings and recordings of the Inquiry Proceedings, the IA/IO must prepare his findings.
22. IA/IO should refrain from giving his suggestions, recommendations to the DA in the Inquiry Findings regarding the penalty / punishment to be imposed upon the CSO/CSE.
23. Inquiry findings should contain Articles of Charge, allegations, PO's brief, CSO's brief and findings of the IA/IO.

At Penalty / Punishment Order Stage:-

24. It shall be ensured that the IA/IO must submit his findings to the DA who shall send a copy of the same along with Memorandum of differences (if any) to the CSO/CSE for his comments. On submission of the comments by the CSO/CSE on the IA/IO Findings, the DA decides the penalty / punishment.
25. In case of Award Staff (Workmen) certain additional steps are involved in ordering a punishment after Inquiry. DA must bear these special provisions/ rules / guidelines in mind while dealing with such cases.
26. Order must be a speaking order. The DA should not simply state whether or not he / she concurs with the findings of the IA/IO. Against each allegation, the DA should explain the analysis of the witnesses, evidences (MEXs & DEXs), submissions produced by both the

parties during the course of Inquiry Proceedings and give his reasoning as to why he concurs or do not concur with the findings of the IA/IO as well as with the contentions of the CSO/CSE. The DA should explain as to how he / she holds the allegation as proved or not proved. It should be made clear as to how misconduct has been committed by the employee as per the articles of charge mentioned in the Charge Sheet.

27. The DA should decide the penalty / punishment by applying his independent mind and solely based on his thinking and judgment. The DA should not award the penalty/ punishment under the influence or pressure of superiors. Any references of the guidance sought from Higher Authorities should strictly be avoided in the penalty / punishment Orders.

28. The DA should decide penalty / punishment commensurate with the committed misconduct.

29. In case of suspended employees, the DA should specify in the penalty / punishment order whether the period of suspension will be treated as on duty or will be treated as suspension. If the period of suspension is confirmed by the DA, it must also mention in the Penalty / Punishment order that the CSO/CSE is not eligible for any kind of payment except for the subsistence allowance already paid to him / her.

30. In Penalty / Punishment Orders involving termination, dismissal and removal of Officers / Employees from Service, the Disciplinary Authorities should specify whether the Gratuity is payable to the Officer/ Employee or the Gratuity is forfeited. However, forfeiture of the Gratuity can only be ordered by the Disciplinary Authority in strict compliance of Section 4 (6) of Payment of Gratuity Act, 1972 which is reproduced hereunder.

4 (6) Notwithstanding anything contained in sub-section (i),-

(a) the gratuity of an employee, whose services have been terminated for any act, wilful omission or negligence causing any damage or loss to, or destruction of, property belonging to the employer, shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused.

(b) the gratuity payable to an employee [may be wholly or partially forfeited].

(i) if the services of such employee have been terminated for his riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part; or

(ii) if the services of such employee have been terminated for any act which constitutes an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed by him in the course of his employment.

Rights of the erring official / CSO / CSE :-

31. Erring Official / CSO /CSE has the right to get adequate opportunity to present his defence, or prove his innocence.

32. CSO/CSE has the right to submit reply as per the stipulated time frame.

33. CSO/CSE has the right to seek / inspect and obtain all the relevant and relied upon documents and list of witnesses.

34. CSO/CSE has the right to engage Defence Representative / Defence Assistant as per the Rules, Regulations and Guidelines in force.

35. CSO/CSE should get equal Opportunity as that of the Presenting Officer in examination / cross examination of evidences & witnesses during the inquiry proceedings.

To sum up, the Disciplinary Action should be the last resort to correct an employee. Where the lapses / irregularities are procedural in nature and does not affect Bank's interest or the indiscipline is not serious in nature other administrative actions may be taken to correct the employee. Where Disciplinary Action becomes inevitable, the above precautionary measures should be kept in mind so as to achieve real purpose of Disciplinary Action.

As already stated, the aforementioned list is not exhaustive but indicative of some common discrepancies not being taken as important while dealing with Disciplinary Action cases. It is hoped that these indicative measures will help in dealing with the Disciplinary Action Cases in a better way.

Chief Manager
Head Office - Disciplinary Action Cell

DOOR TO DOOR CAMPAIGN

Staff members of all branches of zone Noida were on field for Customer contact . Officials from Zonal Office were deputed for coordination and co operation. Few of the photographs are posted here



भ्रष्टाचार-मूल तथा उन्मूलन



देवेन्द्र कुमार

सामान्य रूप से रिश्वतखोरी या गैर कानूनी तरीके अर्थात् अवैध रूप से कमाए गए धन को ही हम भ्रष्टाचार की श्रेणी में मानते हैं जबकि इसकी परिधि काफी व्यापक है। शब्दशः देखें तो भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण करना या अपने आचरण से भ्रष्ट होना। भ्रष्टाचार सामाजिक, नैतिक या फिर संवैधानिक भी हो सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा दूसरे व्यक्तियों को अनैतिक आचरण अथवा गैर कानूनी तरीकों से लाभ पहुंचाना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसमें रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद, सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग, सिफारिश, दिए गए दायित्व का निर्वाह न करना, चोरबाजारी, जमाखोरी व प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का उल्लंघन इत्यादि शामिल हो सकते हैं। धर्म का सहारा लेकर लोगों को पथभ्रमित करना तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करना भी भ्रष्टाचार का ही रूप है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति सदैव न्याय की अनदेखी करता है। हमारे देश के लिए यह विडंबना है कि युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र जैसे धर्मनिष्ठ शासक जिन्होंने जन-कल्याण और देश की रक्षा व स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन महात्माओं की पावन धरती पर आज भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप, आकार और स्थान में अपना अस्तित्व संजोए हुए है। इतना ही नहीं दिन-ब-दिन इसका स्वरूप विकराल होता जा रहा है।

भ्रष्टाचार को हम दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, प्रथम नैतिक भ्रष्टाचार और दूसरा प्रशासनिक। नैतिक भ्रष्टाचार को हम सामाजिक रूप से भ्रष्ट होना भी कहते हैं अर्थात् जो सामाजिक नियम-कायदे हैं उनका पालन न करना, जैसे अपने माता-पिता, गुरु, वरिष्ठ जनों का तिरस्कार करना अथवा सामाजिक परंपराओं व सामाजिक आस्थाओं का अनादर। समाज स्वीकृत नियमों का उल्लंघन करना नैतिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। दूसरे प्रकार का भ्रष्टाचार वह होता है जिसमें सरकार या प्रशासन द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करके अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की जाती है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की संख्या तथा उनका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। इसमें मंत्री से लेकर संतरी और चौकीदार से लेकर नौकरशाह तक शामिल होते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर सर्वाधिक विचार-विमर्श होता है क्योंकि इसमें रिश्वत लेन-देन के अवसर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।

भ्रष्टाचार के मूल में अनेक कारण हैं जिसमें सबसे प्रमुख है व्यक्ति में असंतोष की प्रवृत्ति। मनुष्य कितना भी कुछ हासिल कर ले परंतु उसकी और अधिक प्राप्त कर लेने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। किसी वस्तु की आकांक्षा रखने पर यदि उसे वह वस्तु सहज रूप से प्राप्त नहीं



होती है तब वह किसी तरह भी उसे हासिल करने के लिए आतुर हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। भ्रष्टाचार का दूसरा प्रमुख कारण है- मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति। बात चाहे एक व्यक्ति की हो या फिर किसी समाज या संप्रदाय की, लोगों में निजी स्वार्थ की भावना परस्पर असामानता को जन्म देती है। यह असामानता आर्थिक, सामाजिक व प्रतिष्ठा के मतभेद को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त देश में चारों ओर व्याप्त सांप्रदायिकता, भाषावाद, भाई-भतीजावाद, जातीयता आदि से पूरित वातावरण भी भ्रष्टाचार के प्रेरणा स्रोत हैं। कई बार परिवेश और परिस्थितियाँ भी भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार होती हैं। हर मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। जीवन यापन के लिए के लिए धन और सुविधाओं की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएँ होती हैं। विगत कुछ दशकों में पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। अमीर लगातार और ज्यादा अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब को अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएँ सदाचार के रास्ते पूरी नहीं होती तो वह नैतिकता पर से अपना विश्वास खोने लगता है और कहीं न कहीं जीवित रहने के लिए अनैतिक होने के लिए बाध्य हो जाता है।

किसी भी देश में भ्रष्टाचार और अपराध से निपटने के लिए कठोर और प्रभावी कानून व्यवस्था का होना तो अति आवश्यक है तथापि प्रभावी मशीनरी द्वारा प्रभावी ढंग से इनका क्रियान्वित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। भ्रष्टाचार का एक अन्य कारण यह भी है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए सरकारी

मशीनरी का ठीक प्रबंधन नहीं होता। शासन ने इसके लिए पूर्व में जरूर कुछ कानून बनाए हैं, जैसेरू सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जनलोकपाल विधेयक, 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। भ्रष्टाचार की जड़ में व्यवस्था सर्वोपरि है और व्यवस्था को सुधारे बिना हम भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं लड़ सकते।

अब बात शिक्षा पद्धति की। शिक्षा देश की विकास और उसे सही दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध केवल कानून बनाकर इसे दूर करना तब तक संभव नहीं है जब तक उसे लोगों के मध्य प्रचारित न किया जाए। इससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है जब तक उसे यदि शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को इसकी जानकारी ठीक प्रकार से नहीं होगी। यदि हम छात्र-छात्राओं को विज्ञान, भाषा, प्रबंध, दर्शन शास्त्र, आध्यात्म की शिक्षा देकर उनका व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं तो क्यों न सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार व उनके आचरण को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों की जानकारी शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में दी जाए।

पश्चिमी शिक्षा पद्धति ने स्कूलों और पाठ्यक्रमों में आत्मिक उत्थान से अधिक भौतिक उत्थान पर बल दिया है जिससे बच्चों में ईमानदारी और नैतिकता के लिए पर्याप्त प्रेरक शक्ति का अभाव देखने को मिलता है। बचपन से ही शिक्षा का मूल ध्येय धनार्जन होता है इसलिए बच्चों का पर्याप्त नैतिक उत्थान नहीं हो पाता है। शिक्षा पद्धति में नैतिक मूल्य, आत्म-नियंत्रण, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य जैसे विषयों का समावेश होना अति आवश्यक है। वर्तमान सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा पद्धति को स्वीकृति प्रदान की है लेकिन उसके क्रियान्वयन व परिणाम में अभी देरी है, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। यह आवश्यक नहीं कि बच्चों को नैतिक शिक्षा केवल विद्यालयों में ही दी जाए। परिवार बच्चों का प्रथम पाठशाला होता है जहाँ उन्हें मूलभूत शिक्षा प्रदान की जाती है। किसी का नैतिक उत्थान अथवा पतन उसके आचरण पर भी प्रभाव डालता है। जब तक हमें अपने जीवन के पहले सोपानों पर सत्य के लिए लड़ने की शक्ति और आत्मबल नहीं मिलेगा तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। दुनिया में उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ावे के साथ नैतिक शिक्षा के प्रति उदासीनता बढ़ी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि नैतिक अथवा सामाजिक भ्रष्टाचार ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मूल कारण है।

वरिष्ठ प्रबंधक
प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

१६ सौ वर्षों का इतिहास

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

NRI DEPOSIT MOBILISATION CAMPAIGN
PSB SAMRIDHI NRI DEPOSIT SCHEME
"WHERE OUR INTEREST RATE MEETS YOUR INTEREST"

Highest interest rate in FCNR (B) Deposit scheme for any tenure
(01/12/2021 to 15/01/2022)

NRE/NRO

- Current Accounts
- Saving Accounts
- Fixed Deposits

**FCNR (B)
(Deposit Rates)**

- USD: 2.11% (5 years)
- GBP: 1.99% (3-4 years) (4-5 years)
- EUR: 0.59% (5 years)
- CAD: 2.64% (5 years)
- AUD: 2.41% (5 years)

*TBC Apply

- Complete waiver on inward remittance charges
- Best conversion rates on inward remittances
- 0.10% to 0.20% additional rate of interest being offered on FCNR (B)

For further details, please contact our nearest Branch or Visit us at: www.punjabandsindbank.co.in

1800 419 8300 (Toll Free)

Follow us @PSBIndOfficial

f t i n i

PSB UnIC – A Unique App for everything you need



Himanshu

Punjab & Sind Bank always try to provide best experience to the customers in every possible way. Digital Banking is the need of the hour and a necessary facility that every bank like to offer to their customers. Increasing access to Internet Facility and growing Smartphone industry leads to further increase the need of the digital banking facility. In the current scenario of COVID pandemic, everyone requested to stay at their home until and unless required to go outside, Digital Banking is the best and useful tool to offer almost everything with just a tap and that too without leaving your home. We have used the term 'Digital Banking' but what it actually mean? Well the term itself describe its meaning, Accessing Banking facility digitally using Internet and electronic Gadget without going to the Bank.

Digital Banking includes offering both cash and non-cash facility but required different Application. There are many digital products like Internet Banking, Mobile Banking, UPI, Doorstep Banking etc. that offers different facility but needs different application. Using these application required different credentials that seems to be a difficult task to remember multiple user id and passwords. To solve all these issues and to make the digital experience smoother, Punjab & Sind Bank launched PSB UnIC facility that combines all these facility under one hood. PSB UnIC (You & I Connected) keeps the customers connected to the Bank all the time (24*7). PSB UnIC offers almost all the possible facilities including Fund Transfers, Account Management, Investment, Social security Schemes, Tax Payment, Bill Payment and many other important facilities. Let's talk about the facilities in details:

THE UNIQUE THING OF PSB UNIC:

PSB UnIC app is a facility that can be accessed using any device, Mobile Phone with Internet facility or you can use it on Internet Browsers on your Desktop PC or Laptop. This is one thing that make this facility unique and useful



as one can access the banking facility anywhere anytime. The PSB UnIC application is available on both Android and iOS platforms and can be accessed on other devices that doesn't support mobile application through <https://psbomnigateway.onlinepsb.co.in/PSB/#/login>.

REGISTRATION PROCESS:

Registration is very easy and only take 5 minutes to start a fresh and amazing digital experience. Registration

process requires Debit card details or Internet banking credentials and can also be done using e-Token facility very soon. Other details that you need to complete your UnIC registration includes Your Customer id, Account Number, Mobile Number and E-mail Id. Once you enter all the details correctly and validate successfully using One time password (OTP), you need to create your login username and password, MPIN and TPIN.

SAFE AND SECURE:

PSB UnIC facility is very safe and secure. There is no compromise on the security and safety of user's information stored in the app. The application is made in such a way that one cannot see your details using the Remote desktop software like Anydesk, Teamviewer etc that are most commonly used tools to make fraud nowadays. Further the web app needs an OTP everytime you need to login to access PSB UnIC facility and the smartphone Application can only be run on the smartphone in which the registered number is active. Punjab & Sind Bank also request the users not to share your account details, debit card details, CVV to anyone including the employee of the bank.

FACILITIES OFFERED BY PSB UNIC:

PSB UnIC offers almost everything that we used to do in our day to day life. What I feel is that being a user of this PSB UnIC, I don't need to go to my Bank now as I used to visit my bank for availing facilities like Passbook printing, Fund transfer to other accounts, to open or close Fixed Deposit or Recurring Deposit, To enquire about my cheques, To get the TDS Certificate, To avail Social Security schemes like PMSBY, PMJJY, APY or to pay my income tax but now I can do all this work in just a single tap and that too staying in my comfort zone. The other facilities that I feel is quite important and useful is managing my Debit Card that includes temporary blocking, upgrading or closing of Debit card anytime anywhere. This is very useful feature as many a time we lost our debit card in our home or office and don't want to hotlist it permanently but want to secure our account from any unauthorized transactions so in this case temporary blocking of the Debit card serves the purpose. Features like investing in Government Schemes like PPF, Sukanya Samridhi Yojana, Senior Citizen Saving Scheme etc, Recharge and Bill Payments will also be available very soon that make the experience more delightful.

My Experience with PSB UnIC is really amazing. I am the one who has been waiting for such facility since my relationship with the bank and I am very delighted after using the PSB UnIC facility. PSB UnIC has changed my whole experience of banking with Punjab & Sind Bank and the same I feel for other PSB customers. Now I only need to visit my bank for depositing cash in my bank account that I do once in 3-4 months, technically I need to visit my bank once in 3-4 months while before PSB UnIC I used to visit 2-3 times in a week. I need to maintain different applications for doing different things like Need UPI app to make upi transaction at local shops and other UPI accepting sites or merchants, Need Mobile banking app to view account statement or to make fund transfers upto Rs.50,000 and need to use Internet Banking facility to make larger fund transfers or payments. PSB UnIC combines all these facilities in One Single Application. I can check my account statement anytime anywhere, make payments to anyone with no time restriction, make FD/RD Online, and many other useful features I already discussed above. The best part of the PSB UnIC is the modern look, rich and colorful experience that I love to see whenever I open the Application. The statement generated through the Application is very colorful and informative. The TDS Certificate generator is the best feature I found in this PSB UnIC Application as the generated PDF gives all the information about the Interest amount I earned and the amount of TDS deducted during the financial year. I definitely recommend PSB UnIC app to all the PSBians. I also make a video on PSB UnIC and uploaded it on YouTube. You can watch the video if you want to know about the registration process and features of PSB UnIC. Just Scan the QR Code below and watch it now.

Thank You Punjab & Sind Bank, MD & CEO sir, ED sir, GMs Sir and all the employees working tirelessly to make the experience of the customers' smoother.



Law and Recovery Department

BRANCH MANAGERS REVIEW MEETING



Branch Review Meeting was held at Jaipur in the presence of our Executive Director Dr Ram Jass Yadav ji.



Punjab & Sind Bank has been facilitated by MD of LIC on 23.11.2021 at Hotel Taj, Kolkata



Highlights of Union Budget 2022-23

The Union Finance Minister Smt Nirmala Sitharaman presented Union Budget 2022-23 on February 01, 2022.

The budget provides impetus for growth along four priorities

1. PM Gati Shakti
2. Inclusive Development
3. Productivity Enhancement & Investment, Sunrise, Opportunities, Energy Transition, Climate Action
4. Financing of Investments

Budget numbers:

- Total expenditure for FY2022-23 is placed at Rs. 39.45 lakh crore.
- India economic growth projected at 9.2% in FY21-22.
- The revised Fiscal Deficit for FY2021-22 is estimated at 6.9 % and for FY2022-23 is estimated at 6.4%.
- For FY23, the Gross Government Borrowing is Budgeted at Rs 14.9 lakh crore and net borrowing requirement is pegged at Rs.11.8 lakh crore

Steps related to Financial Sector and Banking:

- Guarantee cover under ECLGS to be expanded by Rs 50,000 Crore to total cover of Rs.5 Lakh Crore. with the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related enterprises
- SCBs to set up 75 Digital Banking Units in 75 districts
- Budget proposed IBC amendments to enhance efficiency of resolution process and facilitating cross-border insolvency resolution.
- Introduction of Digital Rupee by the Reserve Bank of India starting 2022-23.
- The government has lowered divestment proceed target by 55% to Rs. 78,000 crore for FY22 and has pegged the same at Rs. 65,000 crore for FY23.

Taxes:

- There is no change in income tax rates for individuals
- Taxation of virtual digital assets: Any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%.

RETAIL LENDING CAMP

On December 12, 2021 Team Zonal Office Delhi-I organised Retail lending camp at Seva Kendra, East Kidwai Nagar



RASTRIYA EKTA DIVAS

AZADI KA AMRIT MAHOTSAV was organised at Zonal Office Bhopal. A pledge was taken by all staff memmbers.



ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित नववर्ष एक जनवरी को मनाया जाता है किंतु विश्व के अलग-अलग देशों में नववर्ष को लगभग 70 अलग-अलग समय पर मनाया जाता है। हमारे देश में भी खान-पान, वेशभूषा, भाषा की विविधता के साथ नववर्ष के शुभारंभ में भी विविधता है। भारतवर्ष में नववर्ष, सर्वाधिक प्रचलित विक्रम संवत् चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है। भारत सरकार ने शक संवत् प्रणाली को अपनाया है। विभिन्न प्रांतों में भी नववर्ष अलग-अलग समय पर मनाया जाता है लेकिन इसके साथ ही पहली जनवरी को नया साल पूरे जोश और जश्न से मनाया जाता है।

गुजरात में नववर्ष 'वेस्तु वरस' दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों को रंगोली तथा फूलों से सजाते हैं।

कर्नाटक में नववर्ष 'उगादि' चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं।

महाराष्ट्र में नववर्ष 'गुढी पाडवा' चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग घर में रंगोली बनाते हैं तथा ध्वजा फहराते हैं।

असम में नववर्ष 'बिहु' बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जात है। इस दिन लोग गाय की पूजा करते हैं तथा ईश्वर की वंदना कर आगामी वर्ष के समृद्ध होने की कामना करते हैं।

उड़ीसा में नववर्ष 'महा विशुव संक्रांति' 13 अप्रैलको मनाया जाता है। इस दिन लोग तुलसी तथा भगवान शिव की पूजा करते हैं तथा राहगीरों की जल-सेवा के लिए घरों के बाहर जल से भरे मटके रखते हैं।

पंजाब में नववर्ष 'वैसाखी' (14 अप्रैल) को 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह की याद में मनाते हैं। इस दिन किसान समृद्ध फसल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

नववर्ष 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ

